THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. SAROJINI MAHISHI): (a) No, Sir. The development of facilities at pilgrim centres is mainly the responsibility of the State Governments. The Central Department of Tourism is, however, constructing Tourist Bungalows at Rameshwaram and Mantrallaya, and a youth hostel at Puri, but these facilities are not primarily intended for pilgrim traffic.

(b) to (d). The proposals relating to provision of facilities for pilgrims in the form of accommodation, water supply, electricity, toilet facilities, medical facilities, construction of approach roads etc. at Sabarimala, Pampa, Aranmula, Varkala, Thiruvallam, Alwaye, Ettumanoor, Vaikom and Nevyattinkara at an estimated cost of Rs. 7.55 crores were received from the Travancore Devaswom Board, which is a statutory body. In view of the constraint on resources and other priorities, the Central Government is not in a position to provide funds to the Devaswom Board for the comprehensive scheme proposed by them.

The Government of Kerala have, however, included the schemes for provision of tourist facilities at Sabarimala and Guruvayaur temples in the State Plan.

New Aerodrome near Cochin

545. SHRI C. K. CHANDRAPPAN:
SHRI C. H. MOHAMMED KOYA:

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision on the report submitted by the investigation team of the Department of Civil Aviation regarding the location of new aerodrome near Cochin;

(b) the names of the places examined by the team and the broad outlines of their findings; and

(c) the basis on which the Government had taken its decision?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. SAROJINI MAHISHI): (a) to (c). The survey reports on various sites are still under evaluation in the Civil Aviation Department.

रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारियों को दी गई अग्रिम राशियों की वापसी

546. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने जिन व्यापारियों को आर्थिक सहायता दी थी, उन्हें धन वापिस करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) उसे कब तक वापिस किया जाना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारियों को दिये गये अग्रिमों को वापिस मांगने के लिए बैंकों को कोई एकमुश्त हिदायतें नहीं दी हैं ; तथापि मुद्रा सप्लाई के काफी विस्तार और बढ़ी हुई कीमतों के सन्दर्भ में वर्तमान काम काज के मौसम में नीति का समझना अधिक ऋण दिये जाने पर अधिकतम सम्भव प्रतिबन्ध लगाने की ओर है । इस नीति को दृष्टि में रखते हुए रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि यद्यपि उत्पादन तथा माल को लाने ले जाने की वास्तविक आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए जो तेजी से ऋण दे कर किया जा सकता है । रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि हाल में निकाली गयी सभी बड़ी रकमों की बारीकी से जांच करें खास तौर से 25 लाख रुपये या उससे अधिक की बड़ी सीमाओं वाली रकमों के सम्बन्ध में और सुझाव दिया कि जहां यह पाया जाय कि तात्कालिक आवश्यकताओं से अधिक रकमें निकाली गयी हैं तो उन्हें वापस मांगा जाय ।